

स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया : एक तुलनात्मक अध्ययन

देवेंद्र

वाणिज्य एवं प्रबंधन

आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विभिन्न विकासोन्मुख योजनाएँ प्रारंभ की हैं। इनमें स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया प्रमुख पहलें हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जबकि मेक इन इंडिया योजना का लक्ष्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है। प्रस्तुत शोध पत्र में दोनों योजनाओं की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, उपलब्धियाँ तथा चुनौतियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों योजनाएँ परस्पर पूरक हैं तथा दीर्घकाल में भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की क्षमता रखती हैं।

मुख्य शब्द

उद्यमिता, नवाचार, विनिर्माण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास

1. प्रस्तावना

आर्थिक विकास के लिए नवाचार और उत्पादन दोनों ही आवश्यक तत्व हैं। भारत की युवा आबादी और तकनीकी क्षमता को देखते हुए सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जो रोजगार सृजन के साथ-साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति को मजबूत करें। मेक इन इंडिया (2014) और स्टार्टअप इंडिया (2016) इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ की गई योजनाएँ हैं।

2. स्टार्टअप इंडिया योजना : अवधारणा एवं उद्देश्य

स्टार्टअप इंडिया का मूल उद्देश्य नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। यह योजना विशेष रूप से उन संस्थाओं को बढ़ावा देती है जो नवीन उत्पाद, सेवा या तकनीकी समाधान विकसित करती हैं।

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह योजना उद्यमियों को वित्तीय सहायता, आसान अनुपालन, और कराधान (Tax) में छूट प्रदान करके एक मजबूत ईकोसिस्टम बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को 'नौकरी मांगने वाले' के बजाय नौकरी देने वाले (Job Creators) बनाना है।

मुख्य उद्देश्य :

1. नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना
2. स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना
3. पंजीकरण एवं नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना
4. कर में रियायत प्रदान करना
5. बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा

प्रमुख प्रावधान :

1. प्रारंभिक वर्षों के लिए आयकर में छूट
2. सरकारी सहायता से वित्तीय समर्थन
3. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली
4. उद्यम बंद करने की सरल प्रक्रिया
5. पेटेंट व ट्रेडमार्क शुल्क में रियायत

3. मेक इन इंडिया योजना : अवधारणा एवं उद्देश्य

मेक इन इंडिया का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह योजना घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित कर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देती है।

मेक इन इंडिया' सितंबर 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Manufacturing Hub) के रूप में विकसित करना है। यह योजना घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में ही उत्पाद बनाने (Manufacturing) के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, रोजगार सृजित हो और भारत "मेड इन इंडिया" उत्पादों का केंद्र बने।

मुख्य उद्देश्य:

1. विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा
3. रोजगार सृजन
4. निर्यात वृद्धि
5. औद्योगिक अवसंरचना का विकास

यह योजना विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, वस्त्र उद्योग आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।

4. तुलनात्मक विश्लेषण

तुलना का आधार	स्टार्टअप इंडिया	मेक इन इंडिया
प्रकृति	नवाचार एवं सेवा आधारित	उत्पादन एवं विनिर्माण आधारित
लक्ष्य समूह	युवा उद्यमी, नई कंपनियाँ	बड़े उद्योग, घरेलू व विदेशी निवेशक
मुख्य फोकस	तकनीक, डिजिटल समाधान	औद्योगिक उत्पादन
रोजगार प्रभाव	लघु एवं मध्यम स्तर	बड़े पैमाने पर रोजगार
आर्थिक प्रभाव	नवाचार इकोसिस्टम मजबूत	औद्योगिक वृद्धि व निर्यात वृद्धि

5. आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव

1. युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित हुई है।
2. तकनीकी स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि हुई है।
3. विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।
4. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में विस्तार हुआ है।
5. ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को गति मिली है।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

वित्तीय संसाधनों की सीमाएँ

- कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
- वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा

7. सुझाव

1. कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए।
2. ग्रामीण उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
3. डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाए।
4. अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाया जाए।

8. निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों योजनाएँ भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जहाँ स्टार्टअप इंडिया नवाचार और नई सोच को प्रोत्साहित करती है, वहीं मेक इन इंडिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती है। यदि दोनों योजनाओं का समन्वित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार। (2014). मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज एवं नीति विवरण। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार। (2016). स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना (Action Plan) दस्तावेज। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), नई दिल्ली।
3. NCERT. (2023). व्यवसाय अध्ययन (Business Studies), कक्षा XI. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
4. आर्थिक सर्वेक्षण। (विभिन्न वर्ष). भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

5. नीति आयोग। (विभिन्न रिपोर्ट्स). उद्यमिता एवं नवाचार से संबंधित रिपोर्ट। भारत सरकार।
6. Reserve Bank of India (RBI). (विभिन्न वर्ष). Annual Report. मुंबई।
7. Ministry of Commerce and Industry. (Various Years). FDI Statistics and Industrial Policy Reports. Government of India.
8. Gupta, C. B., & Khanka, S. S. (2018). Entrepreneurship and Small Business Management. Sultan Chand & Sons, New Delhi.
9. Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). Entrepreneurship. McGraw Hill Education.
10. Drucker, P. F. (2006). Innovation and Entrepreneurship. Harper Business.
11. Singh, A., & Sharma, R. (2020). "Impact of Startup India Scheme on Indian Economy." International Journal of Research in Commerce and Management.
12. Kumar, S. (2019). "Make in India: Opportunities and Challenges." Journal of Business and Economic Development.